

श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्रीश्री भजनलाल शर्मा
माननीय मुख्यमंत्रीसत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

विकसित राजस्थान की ओर बढ़ते कदम

पेयजल

- ग्रामीण क्षेत्रों में 20 लाख घरों में पेयजल कनेक्शन
- शहरी क्षेत्र में पेयजल के हेतु अमृत 2.0 योजना में 5 हजार 123 करोड़ रुपये के कार्य
- मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन (शहरी) में 5 हजार 830 करोड़ रुपये के कार्य
- 1000 ट्यूबवेल व 1500 हैंडपंप

राम जल सेतु लिंक परियोजना (संशोधित PKC-ERCP)

- 9 हजार 416 करोड़ रुपये के कार्यदिश जारी
- 12 हजार 64 करोड़ रुपये की निविदाएँ जारी
- 12 हजार 807 करोड़ रुपये की स्वीकृति जारी
- आगामी वर्ष में लगभग 9 हजार करोड़ रुपये के नवीन कार्यों की शुरुआत
- Rajasthan Water Grid Corporation में लगभग 4 हजार करोड़ रुपये के कार्य

ऊर्जा

- मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के लाभान्वितों के घरों पर निःशुल्क सोलर प्लांट्स लगाकर 150 यूनिट्स बिजली प्रतिमाह निःशुल्क
- 6 हजार 400 मेगावाट से अधिक अतिरिक्त ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य
- 5 हजार 700 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन के नए कार्यों की शुरुआत

सड़क

- 6 हजार करोड़ रुपये की लागत से 21 हजार किमी. नॉन-पेचेबल सड़कों में सुधार
- 5 हजार करोड़ रुपये से अधिक की लागत से बनेंगे हाईवे, बाईपास, ब्रिज एवं एलिवेटेड रोड
- PMGSY के अंतर्गत 1600 बसावटों को जोड़ा जाएगा
- 5 हजार से अधिक आबादी वाले 250 ग्रामीण कस्बों में अटल प्रगति पथ
- सड़क सुरक्षा के लिए हाइवे पर जीरो एक्सीडेंट जोन व 50 ब्लैक स्मॉट का सुधार कार्य
- 15 शहरों में रिंग-रोड के निर्माण हेतु डीपीआर बनेगी
- हाईवे पर 20 ट्रैमा सेंटर्स के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान, साथ ही 25 Advanced Life Support Ambulances भी उपलब्ध होगी

लाखों युवाओं को सौगात

- आगामी वर्ष में 1.25 लाख सरकारी पदों पर भर्ती
- निजी क्षेत्र में एक लाख 50 हजार युवाओं को रोजगार
- 500 करोड़ रुपये का विवेकानन्द रोजगार सहायता कोष
- 'विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना' में 2 करोड़ रुपये तक के ऋण पर 8 प्रतिशत ब्याज अनुदान

ग्रामीण विकास

- मनरेगा के अंतर्गत 3 हजार 400 लाख मानव दिवसों का सृजन
- स्वामित्व योजना में 2 लाख परिवारों को नए पट्टे
- दादूदयाल घुमन्तू सशक्तिकरण योजना में 25 हजार परिवारों को पट्टे
- पंचगौरव योजना को गति देना, 550 करोड़ रुपये का प्रावधान
- एससी/एसटी कल्याण के लिए एससीएसपी एवं टीएसपी फण्ड की राशि बढ़ाकर 1750 करोड़ रुपये

वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना

- 6 हजार वरिष्ठजनों को हवाई मार्ग से तथा 50 हजार को ए.सी. ट्रेन से तीर्थ यात्रा

सामाजिक सुरक्षा

- विभिन्न वर्गों के पात्र को देय पेंशन बढ़ाकर एक हजार 250 रुपये प्रतिमाह
- विमुक्त, घुमन्तू और अर्द्ध-घुमन्तू समुदायों के लिए 'दादूदयाल घुमन्तू सशक्तिकरण योजना'
- बालिकाओं को शिक्षा में प्रोत्साहन के लिए 35 हजार स्कूटी वितरण का लक्ष्य
- खाद्य सुरक्षा हेतु 10 लाख नवीन Units NFSA लाभान्वित के रूप में जोड़ना
- 5 हजार उचित मूल्यों की दुकानों पर अन्नपूर्णा भण्डार

महिला

- 20 लाख महिलाओं को लखपति दीदी की श्रेणी में लाये जाने का लक्ष्य
- 3 लाख लखपति दीदियों को आगामी वर्ष में 1.5 प्रतिशत ब्याज दर पर 1 लाख रुपये तक का ऋण
- मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना-आंगनबाड़ी पर सप्ताह में 5 दिवस दूध
- गर्भवती महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री किट योजना की शुरुआत

नगरीय विकास

- शहरी क्षेत्र में पंडित दीनदयाल उपाध्याय शहरी विकास योजना के तहत लगभग 12 हजार 50 करोड़ रुपये के कार्य
- 500 Pink Toilets का निर्माण
- समस्त शहरों में 50 हजार स्टीट लाइट्स
- सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र से अम्बाबाड़ी एवं विद्याधरनगर (टोडी मोड़ तक) जयपुर मेट्रो का कार्य
- शहरी क्षेत्रों में 500 नई बसें उपलब्ध
- 100 अत्याधुनिक Robotic-Three-One सीवरेज सफाई मशीनें

सुशासन

- प्रथम चरण में 3 हजार से अधिक जनसंख्या वाले पंचायत मुख्यालयों में अटल ज्ञान केन्द्र
- Ambedkar Institute of Constitutional Studies and Research की स्थापना
- 8 नए जिलों में विभिन्न विभागीय कार्यालयों की स्थापना के लिए एक हजार करोड़ रुपये

हरित बजट

- राज्य का प्रथम हरित बजट (Green Budget)
- Circular Economy के व्यापक प्रसार के लिए Rajasthan Circular Economy Incentive Scheme-2025
- मिशन हरियाळो राजस्थान के अंतर्गत 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य
- लघु एवं सीमान्त कृषकों को बैलों से खेती पर प्रोत्साहन राशि के रूप में 30 हजार रुपये प्रतिवर्ष
- 250 करोड़ रुपये राशि की 'हरित अरावली विकास परियोजना'
- स्वयं सहायता समूह की 25 हजार महिलाओं को सोलर दीदी के रूप में प्रशिक्षण
- एक लाख लाभार्थियों को निःशुल्क Induction Cook Top-Cooking System वितरण का लक्ष्य

औद्योगिक विकास

- निवेश सुविधा के लिए 'सिंगल विंडो - वन स्टॉप शॉप'
- Service Sector में निवेश हेतु Global Capability Centre (GCC) Policy
- Trading Sector के विकास एवं संवर्द्धन हेतु Rajasthan Trade Promotion Policy
- DMIC (Delhi Mumbai Industrial Corridor) से लिंक कर 2 Logistics Parks

कृषि बजट

- आगामी वर्ष में 35 लाख से अधिक किसानों को 25 हजार करोड़ रुपये ब्याज मुक्त फसली ऋण वितरण का लक्ष्य
- किसान सम्मान निधि की राशि अब 9 हजार रुपये प्रतिवर्ष
- राजस्थान कृषि विकास योजना में 1 हजार 350 करोड़ रुपये
- गेहूँ के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर प्रति क्विंटल बोनस राशि बढ़ाकर 150 रुपये
- Micro Irrigation के लिए एक लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में प्रावधान
- आगामी वर्ष में 3 लाख 50 हजार हेक्टेयर में Drip एवं Sprinkler Irrigation System के लिए अनुदान
- 25 हजार Farm Ponds, 10 हजार डिग्गियों, 50 हजार सौर पम्प संयंत्रों तथा 20 हजार किलोमीटर सिंचाई पाइप लाइन के लिए 900 करोड़ रुपये का अनुदान
- आगामी वर्ष 1 लाख हेक्टेयर में ड्रोन के माध्यम से नैनो यूरिया एवं नैनो डीएपी का छिड़काव पर प्रति हेक्टेयर 2 हजार 500 का अनुदान

पशुपालन एवं डेयरी

- 'मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना' में श्रेणीवार बीमित पशुओं की संख्या दोगुनी
- एक हजार नवीन सहकारी समितियों/दुग्ध संग्रह केन्द्रों की स्थापना
- मिल्क उत्पाद, डेयरी प्लांट की प्रोसेसिंग एवं पशु आहार संयंत्रों के क्षमता वर्धन हेतु 540 करोड़ रुपये
- गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना में 2.50 लाख लाभार्थियों की बढ़ोतरी
- गोशालाओं तथा नंदीशालाओं हेतु प्रति पशु देय अनुदान को बढ़ाकर 50 रुपये प्रतिदिन

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

- समस्त जिला चिकित्सालयों में Diabetic Clinics
- गंभीर/असाध्य रोगों के उपचार के लिए Day Care Centres भी समस्त जिला चिकित्सालयों में प्रारम्भ
- प्रदेश को TB मुक्त बनाना, प्रत्येक CHC पर Digital X-ray Machine, TRU-NAAT (ट्रू-नॉट) व CB-NAAT (CB-नॉट) Machine की उपलब्धता
- 'Fit Rajasthan' अभियान, 50 करोड़ रुपये के प्रावधान
- नवीन आयुष नीति, गांवों को आयुष्मान आदर्श ग्राम घोषित कर 11 लाख रुपये प्रोत्साहन राशि
- निःशुल्क जाँच एवं दवा हेतु 3 हजार 500 करोड़ रुपये का 'MAA कोष' का गठन
- MAA नेत्र वाउचर योजना की शुरुआत
- 70 वर्ष आयु से अधिक के वृद्धजनों को आवश्यकतानुसार घर पर ही निःशुल्क दवा

कार्मिक कल्याण

- समस्त मानदेय कर्मियों के मानदेय में आगामी वर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि
- NFSA राशन वितरण का कार्य संभाल रहे Dealers के कमीशन में भी 10 प्रतिशत वृद्धि
- न्यायिक सेवा के पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स को 70 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर 5 प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता
- पंचायती राज एवं नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधियों के मानदेय में भी आगामी वर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि

एस.आई. भर्ती पर दो माह में निर्णय ले सरकार, फील्ड पोस्टिंग पर रोक जारी रहेगी

हाई कोर्ट ने अतिरिक्त महाधिवक्ता से यह भी कहा कि 2 मई को राज्य सरकार के निर्णय की जानकारी दें

—यादवेंद्र शर्मा—
जयपुर, 21 फरवरी। राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती-2021 पेपर लीक मामले में राज्य सरकार को दो माह में निर्णय लेने को कहा है। अदालत ने अतिरिक्त महाधिवक्ता को कहा कि वे 2 मई को राज्य सरकार के निर्णय से अदालत को अवगत कराए। अदालत ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार किसी भी तरह का निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगी, लेकिन मामले में दिए गए यथास्थिति के आदेश जारी रहेंगे और किसी को भी फील्ड पोस्टिंग नहीं दी जाएगी। जस्टिस समीर जैन को एकलपीठ ने यह आदेश कैलाश चन्द्र शर्मा व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

- मामले के जानकार वकीलों का कहना है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के कई निर्णयों में कहा गया है कि अगर पेपर लीक के कारण अवांछित लाभ पाने वाले अभ्यर्थियों को सामान्य अभ्यर्थियों से पृथक किया जा सकता है, तो अपराधी को पकड़ा जाए, पर, उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को नहीं हटाया जाए।
- कई अदालतों के ऐसे भी फैसले हैं, जिनमें कहा गया है कि पेपर लीक का अगर व्यापक प्रभाव नहीं हुआ है तो परीक्षा को रद्द न किया जाए।
- अदालत के आदेशानुसार, अगले दो माह तक भी एस.आई. भर्ती पेपर लीक मामले में जांच जारी रहेगी।

सहित अन्य कार्रवाई की जा सके। इस पर अदालत ने कहा कि यथास्थिति का आदेश जारी रहेगा, लेकिन सरकार मामले में कोई भी निर्णय लेने को स्वतंत्र रहेगी। दूसरी ओर याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता हेरेंद्र नील ने कहा कि भर्ती में पेपर लीक को लेकर राज्य

सरकार के पास पर्याप्त रिकॉर्ड हैं और वह एक सप्ताह में इस पर निर्णय ले सकती है। वहीं सफल अभ्यर्थियों की ओर से कहा गया कि पेपर लीक क्लेम में हमारी सिलिलता नहीं मिली है। हम में से कुछ अभ्यर्थी तो दूसरी सरकारी नौकरी छोड़कर आए हैं। ऐसे में

यदि भर्ती रद्द हुई तो हमारे साथ अन्याय होगा। सफल चयनित अभ्यर्थियों की ओर से पैरवी कर रहे वकीलों का कहना था कि उनके मोव्जकिल आर.ए.एस. व सहयोगी सेवाओं की परीक्षा में भी उत्तीर्ण हुए थे, परन्तु एस.आई. भर्ती परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद उन्होंने वहां पदभार नहीं संभाला। इन एस.आई. भर्ती में उत्तीर्ण हुए अभ्यर्थियों का यह भी कहना है कि उनका नाम पूर्व में किसी भी विवाद या गैरकानूनी गतिविधि से नहीं जोड़ा गया है।

इस मामले को जानने वाले वकीलों का कहना है इलाहाबाद हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के कई निर्णय हैं जिनमें कहा गया है कि 'पेपर लीक' से जुड़े ऐसे मामले जहां 'पेपर लीक' के कारण अवांछित लाभ पाने वाले अभ्यर्थियों को सच्चे व आम अभ्यर्थियों से पूरी तरह पृथक किया जा सकता है, वहां मुजरिमां को पकड़ा जाए, परन्तु अन्य उत्तीर्ण हुए अभ्यर्थियों को हटाया नहीं जाए।

हाईकोर्ट ने पूर्व में लगाया स्टे हटाकर राज्य सरकार को निर्देश दिया।

यचिकाकर्ता के वकील सुनील कुमार सिंगोदिया ने अदालत को कहा कि राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम 1965 को 23 मई 2022 में संशोधित किया गया था, जिसके अनुसार फार्मसी पद पर नियुक्ति के लिये नियुक्ति बोर्ड द्वारा लिखित परीक्षा संचालित की जाएगी और लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक और बोनस अंकों (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

के अंक में प्रकाशित एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए, उन्होंने कहा कि यह सच सामने आ गया है कि 21 मिलियन डॉलर का यू.एस.ए.आई.डी. फंड भारत को नहीं, बल्कि बॉलीवूड को दिया गया था। सरकारी दस्तावेज सिद्ध कर रहे हैं। मोदी जी के घनिष्ठ मित्र टुम्प ने इरादतन या गैर-इरादतन डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिसिएंसी (डीओजीई) के जरिए यह भूल की थी।

मदन राठौड़ कल वापस भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे

जयपुर, 21 फरवरी। मदन राठौड़ का भाजपा प्रदेशाध्यक्ष बनना तय हो गया है। शुक्रवार को पार्टी कार्यालय में प्रदेशाध्यक्ष पद के लिए नामांकन पत्र भरा गया। मदन राठौड़ के अलावा किसी भी दूसरे नेता ने फॉर्म नहीं भरा। ऐसे में उनका प्रदेशाध्यक्ष बनना फाइनल है। हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा शनिवार सुबह 11 बजे होगी।

इससे पहले, मदन राठौड़ के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी, शहर जिला अध्यक्ष अमित गोयल सहित पांच प्रस्तावक बने। शाम साढ़े 4 बजे तक नामांकन भरे गए। इसके बाद नामांकन पत्रों की जांच की गई।

दिल्ली की निवर्तमान व वर्तमान मु.मंत्री के बीच छींटकशी शुरु हुई

पूर्व मु.मंत्री आतिशी मारलीना ने भाजपा की नवगठित सरकार पर आरोप लगाया, उसने दिल्ली की सहायता देने का चुनावी वायदा पूरा नहीं किया

—श्रीनंद झा—
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—
नई दिल्ली, 21 फरवरी। दिल्ली की पूर्व एवं वर्तमान मुख्यमंत्रियों के बीच शब्द-बाण चलना शुरू हो गये हैं। निवर्तमान मुख्यमंत्री आतिशी मारलीना ने भाजपा पर आरोप लगाया है कि उसने महिलाओं को 2,500 रूपए की वित्तीय सहायता देने की योजना की घोषणा न करके अपना चुनावी वादा तोड़ दिया है। ज्ञातव्य है कि भाजपा ने ऐसा चुनावी वादा किया था। वर्तमान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पलटवार करते हुये कहा कि आप नेता को भाजपा से प्रश्न करने का कोई अधिकार नहीं है।

उन्होंने कहा, "अब दिल्ली की चिंता हम करेंगे तथा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में दिल्ली की जनता को उसके अधिकार मिलेंगे।"

नव निर्वाचित मु.मंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि भाजपा सरकार ने अपनी पहली कॅबिनेट मीटिंग में आयुष्मान भारत योजना की स्वीकृति देकर, दिल्ली के हर नागरिक को दस लाख रूपये का लाभ पहुंचाया। अतः अब आप पार्टी को भाजपा से दिल्ली की जनता की मदद पर सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं बनता और अब हम दिल्ली व उसकी जनता की भलाई की चिंता करने के लिए पर्याप्त हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरुवार को हुई मंत्रिमंडल की पहली बैठक में, दिल्ली सरकार ने आयुष्मान भारत योजना को मंजूरी दी थी, जिसे आप सरकार ने रोक दिया था।

मुख्यमंत्री गुप्ता ने कहा, "हमने पद संभालने के पहले दिन ही, दिल्ली की जनता को 10 लाख रूपए का लाभ दिया है।" रेखा गुप्ता ने नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार के 7 में से दो सदस्य अर्थात् 29 प्रतिशत अरबपति हैं। सभी सात मंत्रियों की औसत सम्पत्ति 56.03 करोड़ रूपए हैं, यह जानकारी इलेक्शन वॉचडॉग एसोसिएशन फॉर डैमोक्रेटिक रिफॉर्मर्स (एडीआर) के एक विश्लेषण से प्राप्त हुई है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा उद्योग मंत्री

दिल्ली का विधानसभा सत्र 24 फरवरी

नयी दिल्ली, 21 फरवरी। दिल्ली विधानसभा का पहला सत्र सोमवार से शुरू होगा, जिसमें विधायकों की शपथ के साथ ही, कैंग की रिपोर्ट को भी सदन पेश होने की संभावना है। यह सत्र तीन दिन, 24, 25 और 27 फरवरी को चलेगा। उल्लेखनीय है कि कैबिनेट की

'आपने अपनी दादी इंदिरा गांधी के नाम पर इस योजना का नाम रखा था'

मंत्री की टिप्पणी पर जूली ने कहा, इंदिरा गांधी के लिये इस तरह की भाषा नहीं बोल सकते

■ इस सत्र में विधायकों के शपथ ग्रहण के साथ सी.ए.जी. की लिखित पृष्ठ 14 रिपोर्ट पेश होने की चर्चा है।

—विधानसभा संवाददाता—
जयपुर, 21 फरवरी। "पिछले बजट 2023-24 में आपने हर बार की तरह अपनी दादी इंदिरा गांधी के नाम पर इस योजना का नाम रखा था।" प्रश्नकाल में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिक मंत्री अविनाश गहलोत ने एक सवाल के जवाब में यह तंज कसा।

मंत्री की इस टिप्पणी पर विपक्ष भडक गया। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मंत्री की टिप्पणी का कड़ा विरोध करते हुए कहा था- यह क्या बकवास है? इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री रही हैं, उनके लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।

इसके बाद, स्पीकर वासुदेव देवनानी ने सोमवार तक के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया। सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद, कांग्रेस के निर्लंबित विधायकों को धेरकर विपक्ष धरने पर बैठ गया।

इसके बाद, स्पीकर वासुदेव देवनानी ने गोविंद सिंह डोटासरा, उप नेता प्रतिपक्ष रामकेश मीणा, अमीन कागजी, जाकिर हुसैन गैसावत, हाकम अली खान और संजय कुमार

को बजट सत्र की बची हुई अवधि के लिए निर्लंबित कर दिया। ज्ञात रहे कि गत वर्ष अगस्त में भी कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर को सस्पेंड किया गया था।

सदन के बाहर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि मंत्री ही सदन नहीं चलाया चाहते। आज पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी जब सदन में गतिरोध बना था, तब इनके मंत्री विधायकों ने मुझे और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को

